भारत और अमेरिका ने शिक्षा के क्षेत्र में चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए इस पहल से भारत में सामुदायिक महाविद्यालयों की स्थापना की जा सकेगी

परंपरागत शिक्षा में अंतर को दूर करने के लिए भारत अपने कदम आगे बढ़ा रहा है और देश में कम से कम 200 सामुदायिक महाविद्यालयों की शुरूआत की पहल की गई है।

मानव संसाधन विकास मंत्री श्री एम.एम. पल्लम राजू ने कहा कि देश में विद्यार्थी समुदाय के आकार के मद्देनजर कम से कम 20,000 सामुदायिक महाविद्यालयों की स्थापना का अवसर है। मौजूदा भारत -अमेरिका उच्चतर शिक्षा वार्ता 2013 के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में चार सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

उन्होंने कहा कि सामुदायिक महाविद्यालयों की प्रगति के संदर्भ में पर्याप्त स्पष्टता है। देश में सामुदायिक महाविद्यालयों की रूपरेखा विकसित करने के लिए मंत्रालय अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कम्यूनिटी कॉलेजेस (एएसीसी) के साथ काम कर रहा है।

भारत में सामुदायिक महाविद्यालयों की स्थापना के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और एएसीसी के बीच सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। बड़े पैमाने पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों (एमओओसी) के कारण शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले बदलाव के मद्देनजर सरकार इस क्षेत्र पर ध्यान देने की योजना बना रही है। इस बारे में आईआईटी बॉम्बे और हार्वर्ड की गैर लाभकारी संस्था एडएक्स तथा एमआईटी के बीच सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके अलावा अमेरिका के संस्थानों के साथ गठजोड़ द्वारा शिक्षकों की क्षमता विकसित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। इन पहलों के माध्यम से सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रणाली अपनाने की कोशिश कर रही है।

(स्रोत-एजेंसियां)